वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



सा°/No.: 5-1(352)/2016-PD

दिनांक/Dated: <u>05</u>.09.2017

07

प्रेषक / From:

संयुक्त सचिव (प्रशासन) Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To:

सी.एस.आई.आर के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालों/संस्थाओं/इकाईयों के निदेशक/प्रमुख The Directors/Heads of all National Labs./Instts./Units of CSIR

# महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार के निम्नलिखित संकल्प को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ हैं।

I am directed to forward herewith the following Resolution for information, guidance and compliance.

क्रम सं.	संकल्प सं. /	विषय/
S. No.	Resolution No.	Subject
01	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एफ. सं. 5(1)-बी(पी.डी.)/ 2017 दिनांक 17.07.2017	जीपीएफ और अन्य समान निधियों के संशोधित ब्याज दर के संदर्भ में
	DoEA, MoF, Government of India F. NO. 5(1)-B(PD)/2017 dated 17.07.2017	Revised interest rate of GPF and other similar funds - reg

भवदीय/Yours faithfully,

-1903- Ama

(विनोद कुमार /Vinod Kumar) अवर सचिव (नीति प्रभाग) / US(PD)

## संलग्न/Encl. :यथोपरि/As above प्रतिलिपि/Copy to:

Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy

### (PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)

F.NO. 5(1)-B(PD)/2017
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)

New Delhi, the 17th July, 2017

#### RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2017-2018, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.8% (Seven point eight per cent) w.e.f. 1st July, 2017 to 30th September, 2017. This rate will be in force w.e.f. 1st July, 2017. The funds concerned are:—

- 1. The General Provident Fund (Central Services).
- 2. The Contributory Provident Fund (India).
- 3. The All India Services Provident Fund.
- 4. The State Railway Provident Fund.
- 5. The General Provident Fund (Defence Services).
- 6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
- 7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
- 8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
- 9. The Defence Services Officers Provident Fund.
- 10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
- Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

(Vyasan R.)
Deputy Secretary (Budget)

To.

The Manager, (Technical Branch) Government of India Press, Faridabad.

#### F.No.5(1)-B(PD)/2017

Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITI Aavog.

#### Copy also forwarded to :-

- 1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
- 2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
- 3. Controller General of Accounts (10 copies).
- 4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
- 5. Financial Adviser of Ministries/Departments (6 copies).
- 6. Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
- 7. Controller General of Defence Accounts.
- 8. Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
- 9. Secretary to Governors/Lt. Governors of all States/Union Territories.
- 10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
- 11. All Members, Staff Side, National Council of JCM.
- 12. NIC For uploading on webhost.

(A.K. Bhatnagar) Under Secretary(Budget) (भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

एफ.संख्या 5(1)-बी(पी.डी.)/2017 भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई, 2017

#### संकल्प

आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2017-2018 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक 7.8% (सात दशमलव आठ प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:-

- 1 सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
- 2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)
- 3 अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि
- 4 राज्य रेलवे भविष्य निधि।
- सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
- 6. भारतीय आयध विभाग भविष्य निधि।
- भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
- भारतीय नौसैना गोदी कामगार भविष्य निधि।
- 9 रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
- 10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
- 2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अस्ति अरि (व्यासन आर.) उप-सचिव (बजट)

सेवा में

प्रबंधक, (तकनीकी शाखा) भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद।

फा.संख्या 5(1)-बी(पी.डी.)/2017

फा. संख्या 5(1)-वा(पा.डा.)/2017 भारत सरकार के सभी मंत्रालयां/विभागों, राष्ट्रपति संचिवालय, उप-राष्ट्रपति संचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा संचिवालय, राज्य सभा संचिवालय, मंत्रिमंडल संचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग को प्रति प्रेषित।

#### निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषित:-

- 1. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।
- अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
- 3. महालेखा नियंत्रक (10 प्रतियां)
- 4. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन यूनिट/अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
- मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार (6 प्रतियां)।
- 6 मंत्रालयों/विभागों के मख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक।
- 7. रक्षा लेखा महानियंत्रक।
- 8. सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
- 9 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-राज्यपाल।
- 10. सचिव स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
- 11. सभी सदस्य स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद।
- 12. एनआईसी वैबहोस्ट हेत्।

(ए.के. भटनागर) अवर सचिव (बजट)